Shri Datar: There is a proposal to that effect, but the question is being considered by the Finance Ministry also.

Shri Gidwani: Are Government aware that the new proposals of the Chief Ministers' Conference will involve more expenditure?

Shri Datar: It is not clear whether they will involve more expenditure but if it comes to that, the question will be considered—provided efficiency is achieved.

Shri Gidwani: Has not the States Minister stated that if Part C States go on spending money like this the question will have to be considered whether they should be continued or they should be abolished?

Sari Datar: The statement has not been made by the States Minister in the way in which the hon. Member has put it.

Shri M. L. Dwivedi: Will the hon. Minister lay on the Table a copy of the recommendations of the Chief Ministers' Conference?

Shri Datar: We shall consider it.

सरबार ए० एस० सहगलः : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंग कि पार्ट सी स्टेट्स जिनकी सालाना ग्रामदनी कम है उनके बारे में क्या विचार किया जा रहा है?

Shri Datar: The Government of India recommend grants, because the ultimate responsibility is on the Central Government so far as the Part C States are concerned.

सरदार ए० एस० सहगल: क्या पार्ट सी स्टेट्स को, जिनकी कि घामदनी कम है, सरकार जो पास की स्टेट्स है उनम मिलाने की कृपा करेगी?

Mr. Deputy-Speaker: It is a suggesof policy.

Mr. Deputy-Speaker: It is a suggestion for action.

Shri N. M. Lingam; May I know the specific difficulties experienced by the Part C States?

Shri Datar: There are numerous questions beginning from the appoint-

ments of personnel and control of service down to the establishment of a common High Court and a common cadre. There are also certain procedural difficulties experienced by them. Government are doing whatever is possible, so far as executive action is concerned, immediately. The question of amending the Part C States Act is also under consideration.

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकता

*१७१८. श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या किला मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

- (क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के हिन्दी विभाग में इस समय कितनी पुस्तकें विद्यमान हैं;
- (ख) क्या हिन्दी के समस्त उपलब्ध साहित्य को इस पुस्तकालय में संग्रहीन करना संभव हो सका है;
 - (ग) यदि नहीं, तो उसके कारण ;
- (ष) पुस्तकालय में इस समय मौजूद ें पुस्तकों (भाषा-वार) की सम्पूर्ण संख्या ; तथा
- (ङ) इस पुस्तकालय पर सरकार द्वाराः किया जाने वाला वार्षिक भावर्त्तक तथा भनावर्त्तक व्यय ?

The Deputy Minister of Natural Resources and Scientific Research (Shri K. D. Malaviya): (a) 4,233 (Up to 12/3/53).

- (b) No.
- (c) The funds available are not adequate t_0 purchase all the books published in Hindi.
- (d) A statement is placed on the Table of the House. [See Appendix XL, annexure No. 7.1
- (e) The expenditure for the year 1952-53 was Rs. 2,93,788 recurring and Rs. 55,000 non-recurring.

श्री एम० एल० द्विबेदी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसे पुस्तकालय के लिए जैसा कि नैशनल लाइबेरी, कलकत्ता है कोई कापी राइट ग्रन्थिकार के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है कि ऐसे पुस्तकालयों को कम से कम एक प्रति तमाम प्रकाशनों की मिल सके। यदि हां, तो कब तक यह विचार परिपक्व होगा?

भी के बी मालबीय: जी हां, कापी राइट ऐक्ट के सुधार के सम्बन्ध में तो विचार हो रहा है लेकिन गवनंमेंट की ला भिनिस्ट्री ने इन पर ऐतराज किया है कि ऐसा करना सम्भवतः हमारे संविधान के धनुसार उचित नहीं होगा कि हम किसी पबलिशर से किताब मांग सके। लेकिन फिर भी धाशा है कि बहुत जल्द ही इस प्रश्न पर कोई निर्णय हो जायगा और तब हम पबलिशर्स से किताबें ले सकेंगे जिस से कि इस लाइ हेरी में पुस्तकों की संख्या ज्यादा हो सके।

श्री एम० एल० हिबेबी: स्या कारण है कि इतने बड़े पुस्तकालय में जहां जैसा कि बयान में दिया हुन्ना है, लगभग साढ़े सात लाख पुस्तक हैं, उनमें हिन्दी के विषयों पर इतनी कम पुस्तकों हैं, मौर स्या इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी कोई विचार किया जा रहा है ?

श्री के बी भालवीय : जी हां, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य से गवनंमेंट की बहुत हमदर्दी है। हम भी चाहते हैं कि हिन्दी पुस्तकों का संग्रह बहुत शीध्र बढ़ जाय। , इस सम्बन्ध में कायवाही की जा रही है। हमें भाषा है कि इस साल जो ५० या ५१ हजार की रकम इसके लिए भालग रखी गयी है उसमें भिषकांग पुस्तकें प्रदेशिक भाषाभी भीर विशेषकर हिन्दी भाषा की होंगी। में माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह जो साढ़े सात लाख किताबे हैं वे पुराने जमाने की हैं जब कि स्तास तौर से मंग्रेजी कितावें इकट्ठी की जाती थीं।

डा॰ सुरेश घन्य: मंत्री महोदय ने प्रभी बतलाया है कि इस राष्ट्रीय पुस्तकालय के हिन्दी विभाग में बहुत कम पुस्तकों हैं। एसी सूरत में क्या यह ठीक नहीं है कि इस पुस्तकालय का नाम राष्ट्रीय,पुस्तकालय के बजाय भन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय रखा जाय?

श्री के० डी० मालबीय : जी नहीं, यह ठीक नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: He ought not to use this occasion for giving vent to humour.

Dr. Suresh Chandra: I am sorry, Sir. I did not mean any mental humour. It is a fact, because this is a national library and there are no national books. Our national language is Hindi and there are very tew books in Hindi.

Mr. Deputy-Speaker: What is the point in the hon. Member misunder-standing what I said? What I said was . this. This occasion should not be used for giving vent to humour. national library has been in existence for several years. It was not started yesterday or the day before. happened that until Hindi was made the national language, there were many other languages which were equally good and important and books in those languages were kept in that Now Hindi been adopted as the national language, the hon Minister has said that attention will be paid to Hindi books. He referred to the idea that there should be an increase made in the number, as much as possible, of Hindi books. On top of it, if the hon. Member asks. "Why don't you call it an inter-State in cary or international library?", then the meaning is clear.

Dr. Suresh Chandra: There are not many national books.

Mr. Deputy-Speaker: Whether there are such books or not, that is not the point. His was an ironical statement, and such statements ought to be avoid-

Dr. Suresh Chandra: I am very sorry if I am understood that way.

Mr. Deputy-Speaker: No. It was meant that way and he was understood correctly.

مستو آف ایجوکیش ایلذ نیچورل وسورسز ایلذ سائنتیدک رسرچ (مولانا آزاد): یه الانبویری آنریبل ممبر کو معلوم هے که سو برس پہلے قائم کی گئی تھی - قدرتی طور پر اس وقت اس کا مقصد یه تها که انگریزی کی زیادہ کتابوں جمع کی جائیں۔ یه انگریزی کی کابیں بھی همارے لئے نہایت قیمتی هیں - اب هم کوشش کر وہے هیں که اس میں هلدی کی کتابیں بھی بوهائی جائیں - لیکن کتابیں بھی بوهائی جائیں - لیکن ظاهر هے همیں دیکھنا هوتا هے که کتنا خرچ هاتم میں هے - هماری کشش یہی ہے که جلد سے جلد اهم کشش یہی ہے که جلد سے جلد اهم کشش یہی ہے که جلد سے جلد اهم

[The Minister of Education and Natural Resources and Scientific Research (Maulana Azad): The hon. Member knows that this Library was established 100 years ago. Naturally, its object was to stock as many English books ag possible. These books are very valuable for us. Now we are making efforts to add Hindi books to it. But it is obvious that we have to look to the financial aspect of the matter also. Our endeavour is to add to the number of Hindi books as early as possible.]

Shri T. K. Chaudhur: Am I to understand with reference to the statement just made by the hon. Mr. Malaviya that there are legal or constitutional difficulties in making the National Library a copyright one?

Shri K. D. Malaviya: No. Sir. I said in compelling the publishers to give us books there is some constitutional difficulty. That matter is under consideration.

• ولانا آزاد نہیں : ایک بل اس قرض سے هم پیش کر رہے هیں -

[Maulana Azad: No we are introducing a Bill for this purpose.] स्त्रास्त्र अधिन्त राम: क्या माननीय मंत्री जी फ़रमावेंग कि इस साल के लिये हिन्दी किताबों के लिये कितना रुपया रखा गया है?

श्री के बी माल की य में ने कहा कि ५५ हजार रुपये ग्रलग रखे गये हैं जिस के मुख्यतः हिन्दी भीर प्रान्त की दूसरी भाषाओं की किता कें खरीदी जावेंगी। इस ५५ हजार में से ग्रलग ग्रलग बटकारा तो नहीं किया गया है, लेकिन में ने कहा कि ग्रधिक से ग्रधिक हिन्दी पुस्तकें खरीदने का प्रबन्ध विभाग कर रहा है।

श्री कुष्माचार्य जोशी: क्या माननीय मंत्री यह बतला सकेंगे कि इस हिन्दी विभाग में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ कितने हैं?

श्री के बी माल बीय : मेरे पास इस की सूचना तो, खेद है, इस समय नहीं है।

श्री एस श्री शामता : क्या में माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि सन् १६५२-५३ में जो ५० हजार रुपये इस लाय केरी को दिये गये हैं किता कें खरीदने के लिये भीर प्रकाशन खरीदने के लिये, उन में से कितनी रक्षम हिन्दी किता कें खरीदने पर खर्च की गयी है ?

श्रीके डी • मालबीय: मेरेपास इस की सूचना इस समय नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो इस की सूचन मैंबाद में उन को देस का हुं।

Mr. Deputy-Speaker: Next question.

श्री एम० एस० द्विवेदी: मेरा एक खोटासा प्रश्न भौर बाकी है।

Mr. Deputy-Speaker: Leave that alone. We are not here having a debate on this matter. Enough has been asked.